क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 195, बुधवार, 08 अगस्त, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

स्कूल बस में सीनियर करते थे मासूम छात्र से छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट में शिकायत दर्ज

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले नौ वर्षीय छात्र के साथ कथित तौर पर तीन अलग-अलग मौकों पर स्कूल बस में तीन सीनियर छात्रों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ये घटनाएं जुलाई के आखिरी सप्ताह में हुईं। पीड़ित छात्र ने सोमवार को इन घटनाओं के बारे में अपनी मां को बताया, जिसके बाद विवेक विहार पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले की जांच कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीड़ित बच्चे ने आरोप लगाया कि स्कूल बस में तीन सीनियर छात्रों ने उसे गलत ढंग से छुआ था। पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी तीनों छात्रों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस गहनता से इस मामले की जांच कर रही है और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कांवड़ियों से भरा ट्रक सहारनपुर में पलटा, 32 लोग घायल, हरियाणा के रहने वाले थे सभी कांवड़िये

सोनीपत। हरियाणा के झज्जर जिले के 35 से अधिक कांवड़ियों से भरा एक ट्रक मंगलवार को बाइक सवार को बचाने की कोशिश में पलट गया जिससे उसमें सवार 32 कांवड़िये घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ है। सभी कांवड़िये हरियाणा के झज्जर जिले के ग्राम गौरिया के निवासी हैं। सहारनपुर के एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि हरियाणा के झज्जर जिले के 35 से अधिक कांवड़िये मंगलवार सुबह एक ट्रक में सवार होकर जल लेने हरिद्वार जा रहे थे, तभी थाना नानौता के अंतर्गत एक बाइक को बचाने के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया जिससे उसमें सवार श्रद्धालु घायल हो गए।

20 किलो सोना और 21 लग्जरी कारों के साथ कांवड़ यात्रा पर गोल्डन बाबा

ट्रक के पलटते ही उसमें सवार लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही नानौता पुलिस और वहां से गुजर रहे कांवड़ियों और गांववालों ने घायलों को निकाला। एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया, जबकि गम्भीर रूप से घायल 15 कांवड़ियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मदद के लिए अकेले पुरुष को बुलाने और फिर उसे लूटने में दो महिलाएं गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने दो महिलाओं को लोगों के साथ लूटपाट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये महिलाओं पहले अकेले जा रहे किसी पुरुष को मदद के लिए आवाज देतीं और फिर जब शख्स उनके पास पहुंच जाता तो उसे लूट लेती थीं। ताजा घटना दिल्ली के मूलचंद मेट्रो स्टेशन की है जहां सोमवार की रात एक बाइक सवार का पर्स लूटकर भाग रही महिलाओं को पुलिस गिरफ्तार किया। गिरफ्तार की गई महिलाओं की पहचान स्वीटी उर्फ पूजा (24) और मुस्कान के रूप में हुई है। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और महिलाओं का पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं के पास पीड़ित शख्स का वालेट भी मिला। दिल्ली पुलिस डीसीपी (नॉर्थ-ईस्ट) चिन्मॉय बिस्वाल ने बताया कि उनकी पेट्रोलिंग टीम मेट्रो स्टेशन के पास तैयात थी तभी देखा कि एक शख्स मदद के लिए चिल्ला रहा है और दो महिलाओं के पीछे भाग रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने महिलाओं का पीछा किया और दौड़कर उन्हें गिरफ्तार किया। पीड़ित शख्स ने शिकायत देते हुए बताया कि वह अपने घर जा रहा था तभी दो महिलाओं ने उसे मदद के लिए बुलाया। जब वह उनके पास पहुंचा और अपनी बाइक रोकी तो एक महिला ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गया। इसी बीच दूसरी मलिहा ने उसका पर्स छीन लिया और फिर दोनों वहां से भागने लगीं। मुस्कान विधवा है महिलाओं ने यह भी खुलासा किया कि पिछले दो-तीन महीने करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को लूट चुकी हैं। हालांकि अभी तक किसी ने ऐसी शिकायत नहीं दी।

गाजियाबाद : बिजली ठेकेदार फर्म के कर्मचारियों से दिनदहाड़े 19 लाख रुपये लूटे

मंगलवार शाम तीन बजे उनकी कंपनी के एरिया मैनेजर विशाल अग्निहोत्री, सेल्स मैनेजर अमित कटियार तथा कर्मचारी वसीम सिद्दीकी वसुंधरा सेक्टर-13 स्थित पीएनबी और एक्सिस बैंक की शाखा से 19 लाख रुपये निकालकर ऑफिस वापस आ रहे थे। तीनों एक ही कार में सवार थे।

ट्रांस हिंडन (एजेंसी)। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर-19 में मंगलवार शाम दो बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने एक बिजली ठेकेदार फर्म के कार सवार तीन कर्मचारियों से 19 लाख रुपये लूट लिए। बदमाशों ने एक कर्मचारी को ब्लेड मारकर घायल भी कर दिया। इसके बाद कर्मचारियों को तमंचा दिखाकर बदमाश लैपटॉप और नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए।

सरकारी विभागों को बिजली के सामान की आपूर्ति करने वाली ठेकेदार फर्म यूनिवर्सल इंटरप्राइजेज का इंदिरापुरम शक्ति खंड-3 में ऑफिस है। कंपनी के निदेशक हितेश कुमार के मुताबिक, मंगलवार शाम तीन बजे उनकी कंपनी के एरिया मैनेजर विशाल अग्निहोत्री, सेल्स मैनेजर अमित कटियार तथा कर्मचारी वसीम सिद्दीकी वसुंधरा सेक्टर-13 स्थित पीएनबी और एक्सिस बैंक की शाखा से 19 लाख रुपये निकालकर ऑफिस वापस आ रहे थे। तीनों एक ही कार में सवार थे। एलिवेटिड रोड के नीचे वसुंधरा सेक्टर-19 में विद्युत सब स्टेशन के ठीक पास एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उनकी कार को ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी।

इसके बाद बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने अपने सिर से हेलमेट उतारकर चालक की सीट पर बैठे अमित के दे मारा। इससे पहले कि कर्मचारी कुछ समझ पाते तभी दूसरी बाइक पर सवार दो और बदमाश वहां आ गए।

चारों बदमाशों ने कर्मचारियों पर पिस्टल तानकर कार की पीछे की सीट पर रखा बैग लूट लिया। इस दौरान बदमाशों ने विशाल को ब्लेड मारकर घायल कर दिया। इसके बाद बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गए।

बैंक के पास से बदमाश के पीछा करने का शक

पीड़ितों के मुताबिक, बदमाश उनके पीछे बैंक के पास से ही लगे हो सकते हैं। लेकिन वह इसका ध्यान नहीं दे पाए। सब स्टेशन के पास जैसे ही ओवरटेक करते हुए बाइक सवार ने हेलमेट उतारकर मारना शुरू किया तब कंपनी कर्मचारियों की समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बदमाशों के जाने के बाद एक कर्मचारी ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी।

चारों बदमाशों ने हेलमेट पहना हुआ था

पीड़ितों के मुताबिक, बाइक सवार चारों बदमाशों ने हेलमेट पहने हुए थे। जिस बदमाश ने कर्मचारी के हेलमेट उतारकर मारा सिर्फ उसका चेहरा ही कर्मचारी देख पाए हैं। अन्य तीनों बदमाशों का चेहरा कर्मचारियों ने देखा नहीं है।

एसएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

लूट की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी वैभव कृष्ण ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर पीड़ित कंपनी कर्मचारियों से बातचीत की।

इसके बाद एसएसपी ने इंदिरापुरम थाना पुलिस को घटना का शीघ्र खुलासा करने का निर्देश दिया। बैंक तथा घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। घटना का शीघ्र खुलासा करने में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं।

इसी साल से लागू होगा फैसला

दिल्ली सरकार ने विधायक निधि 4 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार ने विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली राशि को सालाना चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

दिल्ली विधानसभा को कैबिनेट की बैठक के निर्णय के बारे में सूचित करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सभी विधायक मांग कर रहे थे कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाया जाए। सिसोदिया ने विधानसभा को बताया कि कैबिनेट ने विधायक निधि को मौजूदा चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का निर्णय किया है।

अब दिल्ली में भी होगा अपना लोक सेवा आयोग, विधानसभा में बिल पास

दिल्ली में एक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्य कराने के लिए एक साल में चार करोड़ रुपये मिलते हैं।

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कैबिनेट का फैसला इसी साल से लागू किया जाएगा।

सिसोदिया ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी में कई भारतीय भाषाओं जैसे तेलुगु, कश्मीरी, मलयालम,

गुजराती समेत अन्य भाषाओं की अकादमी के अलावा विदेशी भाषा अकादमी स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

>>> सात बदमाश गिरफ्तार

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़

ग्रेटर नोएडा। एजेंसी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर वाहन चालकों से लूटपाट और चोरी करने वाले सात बदमाशों तथा इनसे माल खरीदने वाले तीन कबाड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके 3 साथी अभी फरार हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी और लूटी गई 23 बैट्री, करीब 7 किलो गांजा तथा अपराध में इस्तेमाल होने वाली तीन गाड़ियां बरामद की हैं। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय पाल ने बताया कि हमें काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे पर सड़क किनारे खड़े होने वाले ट्रकों और अन्य वाहनों की बैट्रियां कुछ बदमाश चालकों से मारपीट करके लूट रहे हैं।

उन्होंने बताया कि घटना की जांच के लिए दादरी थाने की पुलिस को लगाया गया। एक सूचना के आधार पर दादरी पुलिस ने सोमवार रात को शमसुद्दीन, जय किशन, लोकेश, वीरपाल, कपिल, कुवरकेश और बबलू नामक सात लुटेरों को गिरफ्तार किया जबकि इनसे लूट का माल खरीदने वाले कबाड़ी नजीर, इस्लामुद्दीन और वसीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने सैकड़ों वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। एसएसपी ने बताया कि इनके तीन साथी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

मेट्रो ट्रेन में फर्श पर बैठने वालों से DMRC ने वसूला 38 लाख रुपये जुर्माना

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली मेट्रो ने पिछले करीब 11 महीनों के दौरान ट्रेन के फर्श पर बैठकर यात्रा करते पकड़े गए लोगों से 38 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया है। यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त जवाब में सामने आई है। गंदगी फैलाने, बाधा उत्पन्न करने, उचित टोकन के बिना यात्रा करने और अधिकारियों के काम में बाधा डालने सहित विभिन्न अपराधों के लिए जून 2017 से मई 2018 के बीच 51,000 लोगों से कुल 90 लाख रुपये वसूल किए गए।

आरटीआई से हुआ खुलासा

एक पत्रकार द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने कहा कि इनमें से सबसे अधिक 38 लाख रुपया फर्श पर बैठने वालों से वसूल किया गया। एक अनुमान के मुताबिक, ट्रेन के फर्श पर बैठने के लिए 19,026 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। मेट्रो ट्रेन के फर्श पर बैठना सार्वजनिक शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है और इसके लिए 200 रुपये का जुर्माना है। डीएमआरसी के मुताबिक, पिछले साल जून से लेकर इस साल मई तक 51,441 लोगों पर जुर्माना लगाया गया और कुल 89,94,380 रुपये वसूल किए गए। मेट्रो की ब्लू लाइन पर ट्रेन की छत पर यात्रा करने का भी एक मामला दर्ज किया गया, जिसके लिए अपराध करने वाले से 50 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

येलो लाइन पर वसूला गया सबसे अधिक जुर्माना

येलो लाइन पर सबसे अधिक जुर्माना 39,20,220 रुपया वसूल किया गया। अन्य अपराध जिसमें जुर्माना वसूल किया गया उनमें टोकन ले जाते हुए।

123वें संविधान संशोधन विधेयक को रास की भी मंजूरी

ओबीसी आयोग को मिला संवैधानिक दर्जा

ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल सोमवार को राज्यसभा से पास हो गया। लोकसभा से ये बिल पहले ही पास हो गया था। संवैधानिक दर्जा मिलने से आयोग एक स्वायत्त संस्था के तौर पर काम कर सकेगा।

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को सोमवार को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में इससे संबंधित संविधान (123वां संशोधन) विधेयक पारित कर दिया। लोकसभा से इसे पहले ही पारित कराया जा चुका है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि इससे पिछड़े वर्ग का सशक्तिकरण होगा और आयोग की शक्तियां भी बढ़ेंगी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है और इसके काम क्या होंगे: ये आयोग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे। इसमें कम से कम एक महिला होगी। आयोग एक स्वायत्त संस्था के तौर पर काम करेगा। ये आयोग पिछड़े वर्गों से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगा। अब पिछड़ी जातियों की समस्याओं का निपटारा हो सकेगा। इस आयोग का गठन 1993 में किया गया था।

ओबीसी तबके में जातियों को जोड़ने या हटाने के लिए राज्यपाल से परामर्श लेने का प्रस्ताव हटा। अब राज्य सरकारों से ही परामर्श लेने का प्रावधान। ओबीसी के उत्थान को लेकर बनने वाली योजनाओं में आयोग की भूमिका में भी बदलाव।

आयोग सलाहकार नहीं बल्कि भागीदार की भूमिका में होगा। आयोग पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भाग लेगा और सलाह देगा। राज्य अपने लिए ओबीसी जातियों का निर्णय करने के बारे में स्वतंत्र हैं। यदि राज्य किसी जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करना चाहते हैं, तो वे सीधे केंद्र या आयोग को भेज सकते हैं। आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से समुदाय के लोगों की विभिन्न जरूरतें पूरी होंगी और कई ऐसी समस्याओं का भी हल हो पाएगा जिनका हल अभी तक नहीं हो सका है।

पिछड़ा वर्ग विधेयक पारित होने को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ऐतिहासिक

पीएम मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित 123वें संविधान संशोधन बिल को संसद की मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए इसे एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया है। बिल पारित होने के तुरंत बाद पीएम ने ट्वीट किया कि यह हमारे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मुझे प्रसन्नता है कि संसद ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले 123 वें संविधान संशोधन बिल को पारित कर दिया है।' इससे देश भर में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बिल के पारित होने से कमजोर वर्गों के हितों के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। इससे कमजोर व शोषित वर्गों के लोगों को न्याय मिलने में मदद मिलेगी।

एनडीए उम्मीदवार हो सकते हैं सांसद हरिवंश

नई दिल्ली, एजेंसी। एनडीए की ओर से जेडीयू सांसद हरिवंश राज्यसभा उपसभापति उम्मीदवार हो सकते हैं। राज्यसभा के उप सभापति का चुनाव इसी सप्ताह नौ अगस्त को होगा और इसके लिए आठ अगस्त बुधवार तक नामांकन किये जा सकते हैं। सदन के सभापति एम. वेंकैया नायडु ने सोमवार को राज्यसभा में इस आशय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सदन के उप सभापति का चुनाव नौ अगस्त को सुबह 11 बजे होगा। इसके लिए नामांकन आठ अगस्त, बुधवार 12 बजे तक स्वीकार किये जाएगें। उन्होंने कहा कि तय सीमा के बाद कोई नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्यसभा के उप सभापति पी जे कुरियन के जुलाई में सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद रिक्त है।

पायलट प्रोजेक्ट शुरू, इमेजिंग जांच की बाट जोह रहे रोगियों की दिक्कतें होगी कम

एम्स में 24 घंटे होंगे एमआरआई,एक्सरे व अल्ट्रासाउंड

नई दिल्ली (एजेंसी)। अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण और संसाधनों से लैस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में बेहतर इलाज की उम्मीद में पहुंचने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। एमआरआई जांच के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

एम्स में एमआरआई जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। एक अगस्त से इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही दिनों में विधिवत यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इस पहल से एमआरआइ जांच की प्रतीक्षा सूची का समय घटेगा। योजना शुरू होने के छह दिन में ही करीब 200 से अधिक मरीजों को जांच की सुविधा प्रदान की गई। बीते रिकार्डस पर यदि नजर डाली जाए तो इतनी संख्या में जांच की अवधि चार से पांच माह तक रहती थी।

छह दिन में 200 मरीजों को मिली सुविधा, आम तौर से इतनी संख्या जांच चार से पांच महीनों में होतीअभी छह महीने से लेकर एक साल तक की वेटिंग

लंबी तारीख से मिलेगी निजात : वर्तमान समय में एम्स में मरीजों को एमआरआई जांच के लिए लंबी तारीखें दी जाती हैं। छह महीने से लेकर एक साल तक की वेटिंग है। प्रतीक्षा सूची इतनी लंबी है कि ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचे ज्यादातर मरीजों को बाहर से एमआरआइ जांच कराने की सलाह भी दी जाती है।

इसका बड़ा कारण एम्स में मरीजों का भारी दबाव है। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती मरीजों को तरजीह दी जाती है।

मशीनों की क्या है स्थिति : एम्स में तीन एमआरआई मशीनें हैं। इनमें री टेस्ला (क्षमता मापने का मात्रक) की दो व 1.5 टेस्ला की एक मशीन शामिल है। री टेस्ला की मशीन उच्च गुणवत्ता की होती है। इन मशीनों से आठ घंटे में प्रतिदिन 25 से 30 मरीजों की जांच होती है। अस्पताल के वार्ड में भर्ती व इमरजेंसी में पहुंचने वाले कई मरीजों को रात में एमआरआई की जरूरत पड़ जाती है। इन तयों को ध्यान में रखते हुए एनएमआर (न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस) विभाग ने इस जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव एम्स प्रशासन को भेजा है। इस पर कार्डियक रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर रेडियोलॉजी व जनरल रेडियोलोजी विभाग से सहमति मांगी गई है।

रेडियोलॉजी विभाग के प्रो. रोहित ने कहा कि इमेजिंग संबंधी जांच रेडियोलोजी के डाक्टर ही करते हैं। अभी तक उन विभागों ने सहमति पत्र जारी नहीं किया है। फिर भी ट्रायल के रूप में सुविधा शुरू कर दी गई है। जल्दी ही विभागों से सहमति मिलने पर व्यवस्थित तरीके से 24 घंटे एमआरआइ जांच होने लगेगी। इससे अधिक मरीजों की जांच हो सकेगी।

अन्य सुविधाएं भी बढ़ेगी : एम्स के निदेशक डा. रणदीप गुलेरिया ने दावा किया कि अन्य विभागों में नैदानिक और इमेजिंग जांच का दायरों बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत कैंसर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं शामिल हैं। मशीनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। रखरखाव के लिए तकनीशियनों की संख्या में इजाफा भी किया जा रहा है।

संपादकीय

समाज विरोधी समाजसेवी

बिहार के मुजफ्फरपुर के बाद उत्तर प्रदेश का देवरिया जिन शर्मनाक कारणों से चर्चा में है उससे यही पता चल रहा है कि अपने देश में बालिका अथवा नारी संरक्षण गृह चलाने का काम धूर्त और लंपट किस्म के लोग भी कर रहे हैं। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि ऐसे समाज विरोधी तत्व पहुंच वाले भी साबित हो रहे हैं। जैसे यह साफ है कि मुजफ्फरपुर के बालिका आश्रय गृह का संचालन एक खराब छवि और दागदार अतीत वाले शख्स के हाथ में था वैसे ही यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि देवरिया के नारी संरक्षण गृह की कमान भी संदिग्ध किस्म के लोगों के हाथ पहुंच गई थी। वे समाजसेवा के नाम पर किस तरह समाज विरोधी काम करने में लगे हुए थे, इसका पता इससे चलता है कि देवरिया के नारी संरक्षण गृह के बारे में लगातार मिल रही शिकायतों के कारण उसे बंद करने के निर्देश देने पड़े थे। जिले के अधिकारियों ने इस निर्देश की अनदेखी करके नाकारापन का परिचय देने के साथ ही यह संदेह भी पैदा किया कि कहीं उन्होंने ढोंगी समाजसेवियों से साठगांठ तो नहीं कर ली थी? सच्चाई जो भी हो, यह अच्छा हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना किसी देरी के देवरिया के जिला अधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्ती दिखाई। और भी अच्छा होगा कि उन्हें उनकी नाकामी के लिए कुछ और दंड दिया जाए। तबादले या निलंबन को यथोचित दंड नहीं कहा जा सकता। समाज और देश को शर्मिंदा करने वाले ऐसे मामलों में सबक सिखाने वाली कार्रवाई की जानी चाहिए-न केवल संरक्षण गृह चलाने वालों के खिलाफ, बल्कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी। 1यह शासन-प्रशासन की नाकामी ही है कि ऐसे तत्व आश्रय स्थल चलाते पाए जा रहे जो एक तरह से सभ्य समाज के लिए शत्रु हैं। आखिर जिला प्रशासन इतने नाकारा कैसे हो सकते हैं कि वे संदिग्ध गतिविधियों वाले किसी संरक्षण गृह की हकीकत न जान सकें? इससे लज्जाजनक और कुछ नहीं हो सकता कि बालिका अथवा नारी संरक्षण गृह में आश्रय लेने वाली लड़कियों और महिलाओं को देह व्यापार में धकेल दिया जाए। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि मुजफ्फरपुर और देवरिया के संरक्षण गृहों की शर्मिंदा करने वाली तस्वीर सामने आने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य राज्य भी इस तरह के आश्रय स्थलों की गहन निगरानी करना सुनिश्चित करें। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि ऐसे स्थल आम तौर पर उपेक्षित ही अधिक होते हैं। दुर्भाग्य से इन स्थलों के प्रति उपेक्षा भाव शासन-प्रशासन में ही नहीं, समाज में भी है। यह संभव नहीं जान पड़ता कि संरक्षण गृह में घोर अनुचित काम होते रहें और आसपास के लोगों को उनके बारे में कुछ भनक न लगे। किन्हीं कारणों से संरक्षण या आश्रय गृहों मे गुजर-बसर करने वाले बच्चों, लड़कियों और महिलाओं को गरिमामय जीवन जीने का अवसर मिले, इसकी चिंता सरकारों के साथ समाज को भी करनी चाहिए। अगर शासन के साथ समाज अपने हिस्से की जिम्मेदारी सही तरह निभा रहा होता तो शायद मुजफ्फरपुर और देवरिया में शर्मसार करने वाले मामले सामने नहीं आए होते।

फूंकनी होगी जान

बैंक/ जयंतीलाल भंडारी

सरकार की रणनीति अगले 3 वर्षों में वर्तमान 21 सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 10-12 करने की है। यकीनन केंद्र सरकार द्वारा सरकारी बैंकों के लिए पुनपरूजीकरण के नये पैकेजों से बैंकों को मजबूत बनाने और डूबते हुए कर्ज से गंभीर रूप से बीमार भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। आशा करें कि सरकार बैंकों के पुनपरूजीकरण के कार्य पर उपयुक्त निगरानी और उपयुक्त नियंतणरखेगी। बैंकों को दी गई भारी-भरकम नई पूंजी के आवंटन की उपयोगिता और प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करेगी कि बैंक इसका इस्तेमाल कितने प्रभावी ढंग से करेंगे और फंसे कर्ज से कैसे निपटेंगे।

हाल ही में 3 अगस्त को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूंजी आधार बढ़ाने और फंसे कर्ज (एनपीए) को वसूलने के प्रयासों के सकारात्मक नतीजे नजर आने लगे हैं। कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में 7 सरकारी बैंकों के सकल एनपीए में 4464 करोड़ रुपये की कमी आई है। इन बैंकों में बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और विजया बैंक शामिल हैं। यह भी कहा गया है कि 31 मार्च, 2018 को सरकारी बैंकों के एनपीए की रकम 8 लाख 45 हजार करोड़ रुपये हो गई है। ऐसे में देश और दुनिया के अर्थ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में बैंकों की जन हितैषी योजनाओं के संचालन संबंधी भूमिका के कारण सरकारी बैंकों के निजीकरण के बजाय सरकारी बैंकों में नई जान फूंकने के और अधिक प्रयास जरूरी हैं। वस्तुत- सरकारी बैंकों में पुनपरूजीकरण का कदम एक बड़ा बैंकिंग सुधार है। इससे सरकारी बैंकों को दोबारा सही तरीके से काम करने का अच्छा मौका मिल रहा है। इससे बैंकिंग व्यवस्था मजबूत बन रही है। पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और इसमें नई जान फूंकने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की हालत को पर्याप्त पुनपरूजीकरण से बेहतर करना सबसे पहली जरूरत है। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण दूसरी जरूरत है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत को इसके लिए गैर-निष्पादित आस्तियों के समाधान को बढ़ाना होगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण वसूली पण्राली को बेहतर बनाना होगा।गौरतलब है कि 17 जुलाई, 2018 को सरकार के द्वारा पांच सरकारी बैंकों पंजाब नैशनल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन ओरवसीज बैंक, आंध्रा बैंक तथा इलाहाबाद बैंक के पूंजीकरण के तहत 11337 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज घोषित किया गया है। इसके पहले 24 अक्टूबर, 2017 तक फंसे कर्ज की समस्या से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अगले दो साल में 2.11 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिया जाना सुनिश्चित किया गया था। यद्यपि बैंक पूंजी बाजार में भी जा सकते हैं, लेकिन सरकारी बैंकों के शेयर मूल्य इतने कम हैं कि सरकारी बैंक शेयर बाजार से भी अपेक्षित पूंजी नहीं जुटा पाएंगे। केंद्र सरकार, सरकारी बैंकों का निजीकरण करते हुए उन्हें निजी हाथों में बेच भी सकती है, लेकिन फिलहाल देश में सरकारी बैंकों को खरीदने की संभावना रखने वाले भरोसेमंद व्यक्ति या संगठन दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन सबके अलावा, सरकारी बैंकों को विदेशियों को भी बेचा जा सकता है, लेकिन इस समय यह देश हित एवं राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं होगा। इस तरह ऐसा कोई उपाय नहीं है, जो एक झटके में बैंकों की हालत सुधार दे और अर्थव्यवस्था की विभिन्न दिक्कतें दूर कर दे। चूंकि सरकार किसी सरकारी बैंक को विफल नहीं होने देना चाहती है, अतएव सरकार बैंकों को जरूरी पूंजी मुहैया कराने की डगर पर आगे बढ़ी है। इससे पूंजी की किल्लत से परेशान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जल्द राहत मिलेगी। नीति आयोग का कहना है कि बैंकों को पूंजी मिलने से कर्ज देना आसान होगा। कर्ज देने की रफ्तार बढ़ने की स्थिति में निजी निवेश में तेजी आएगी।इतना ही नहीं सरकार की जनहित की योजनाएं सरकारी बैंकों पर आधारित हैं। देश भर में चल रही करीब 1100 कल्याणकारी स्कीमों के लिए धन की व्यवस्था करने और उन्हें बांटने की जिम्मेदारी सरकारी बैंकों को सौंप दी गई है। सरकारी बैंकों द्वारा मुद्रा लोन, एजुकेशन लोन और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए धड़ाधड़ कर्ज बांटा जा रहा है। आधार कार्ड के अपडेशन से लेकर पैन कार्ड और अन्य तरह के दस्तावेज भी यहां तैयार हो रहे हैं। बैंकरों को गांव-गांव जाकर न केवल लोन बांटना है, बल्कि पुराने लोन की रिकवरी भी करनी है। नतीजतन, बैंक ऑफिसर अपना मूल काम यानी कर बैंकिंग छोड़कर बाहर घूम रहे हैं। चूंकि बीमा या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक खाता जरूरी है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की भारी कमी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2018 तक जनधन योजना के तहत 31.44 करोड़ खाते हैं। 2014 से 2017 के बीच दुनिया में 51 करोड़ खाते खुले जिनमें से 26 करोड़ खाते केवल भारत में जन-धन योजना के अंतर्गत हैं। भारत में इस अवधि में 26 हजार नई बैंक शाखाएं भी खुली हैं। ऐसे में भारत की नई बैंकिंग जिम्मेदारी बैंकों के निजीकरण से संभव नहीं है। सरकारी बैंकों को ही सक्षम बनाना जरूरी है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 23 अगस्त, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक बैंकों के एकीकरण में तेजी लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस कवायद का मकसद सरकारी बैंकों को सुदृढ़ करना है। सरकार की रणनीति अगले 3 वर्षों में वर्तमान 21 सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 10-12 करने की है। यकीनन केंद्र सरकार द्वारा सरकारी बैंकों के लिए पुनपरूजीकरण के नये पैकेजों से बैंकों को मजबूत बनाने और डूबते हुए कर्ज से गंभीर रूप से बीमार भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। आशा करें कि सरकार बैंकों के पुनपरूजीकरण के कार्य पर उपयुक्त निगरानी और उपयुक्त नियंतणरखेगी। बैंकों को दी गई भारी-भरकम नई पूंजी के आवंटन की उपयोगिता और प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करेगी कि बैंक इसका इस्तेमाल कितने प्रभावी ढंग से करेंगे और फंसे कर्ज से कैसे निपटेंगे। साथ ही, बैंकों के पुनपरूजीकरण से दोहरी बैलेंस शीट की समस्या कितनी हल होगी। इन बातों पर प्रभावी नियंतण्रके साथ-साथ सरकार को सरकारी बैंकों से संबंधित लंबे समय से लंबित प्रशासनिक सुधारों पर भी ध्यान देना होगा। इस तरह बैंकों के पुनपरूजीकरण के साथ-साथ बड़े और मजबूत सरकारी बैंकों को आकार देने की उपयुक्त रणनीति लाभप्रद होगी। ऐसा होने पर ही बैंकों में नये निवेश से छोटे बड़े उद्योग-कारोबार के साथ-साथ आम आदमी भी लाभान्वित होंगे। साथ ही, सार्वजनिक बैंक मजबूत बनकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए अर्थव्यवस्था को गतिशील बना सकेंगे।

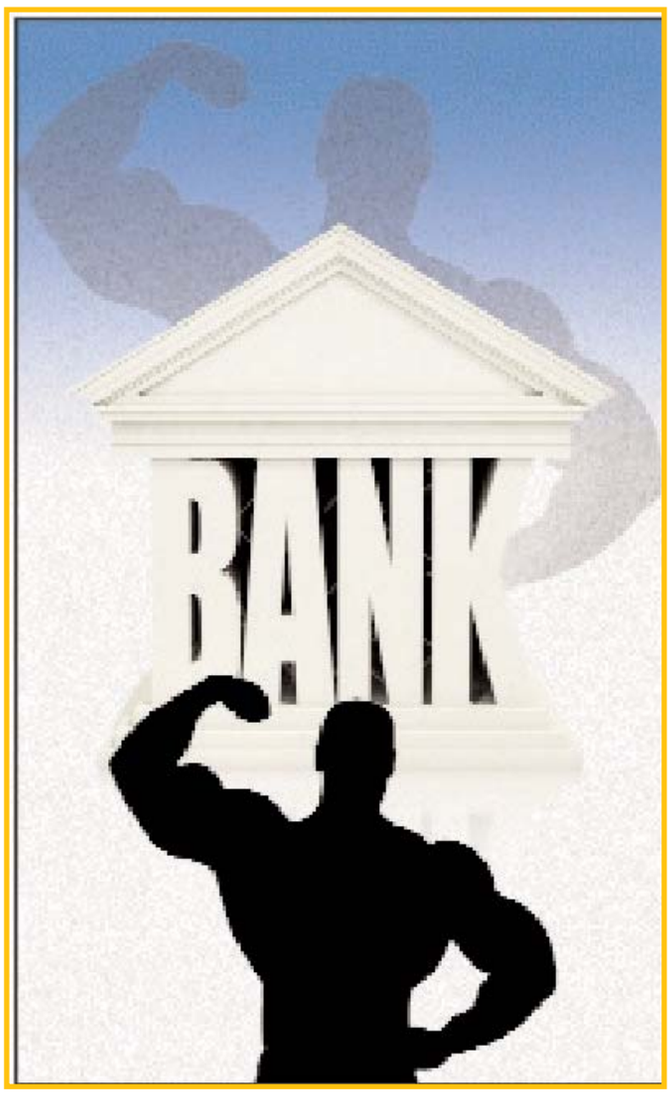

आज का राशीफल

मेष आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा में अपने बहुमूल्य सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। भाई या पड़ोसी का सहयोग रहेगा।

वृषभ व्यावसायिक योजना सफल होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। त्वचा उदर या वायु विकार की संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मिथुन जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। किया गया प्रयास सफल होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। परिश्रम अधिक करना होगा।

कर्क पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नए अनुबंध प्राप्त होंगे। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

सिंह पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।

कन्या व्यावसायिक व पारिवारिक योजना सफल होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। भाई या पड़ोसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आयेगी। अनचाही यात्रा या विवाद में फंस सकते हैं।

तुला बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी अपेक्षित है। विरोधी शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट देंगे। पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पिता या संबंधित अधिकारी से तनाव मिलेगा।

वृश्चिक पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। मैत्री संबंध में प्रगाढ़ता आयेगी।

धनु शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। छोटी-छोटी बातों पर उत्तेजना हो सकती है। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे।

मकर रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। नेत्र विकार की संभावना है। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। रोग और विरोधी बढ़ेंगे। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें।

कुम्भ पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। क्रोध व भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टकारी होगा।

मीन जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

लंबा है असम की अस्मिता का संघर्ष

- एनके त्रिपाठी

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का अंतिम मसौदा सामने आने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या एक बार फिर सुर्खियों में है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि असम के मूल निवासी दशकों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। मैं भारतीय पुलिस सेवा में रहा हूं और अपने इस सेवाकाल के दौरान मुझे असम के लोगों द्वारा घुसपैठियों के खिलाफ संघर्ष को करीब से देखने का मौका भी मिला। मुझे याद है कि मार्च 1980 में मैं कमांडेंट के तौर पर एसएएफ की 24वीं बटालियन को मय हथियार, गाड़ियां व तमाम साजोसामान लेकर स्पेशल ट्रेन से गुवाहाटी पहुंचा था। 27 नवंबर 1979 से पूरे असम में जबर्दस्त आंदोलन चल रहा था और जगह-जगह धरना-प्रदर्शन हो रहे थे। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन तथा ऑल असम गण संग्राम परिषद द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी में चुनाव प्रक्रिया को ठप कर दिया गया था। केंद्र में बैठी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की तंद्रा तब टूटी, जब आंदोलनकारियों ने गुवाहाटी की नारंगी रिफायनरी से बिहार स्थित बरौनी रिफायनरी को आने वाली पेट्रोलियम की पाइप लाइन को अवरुद्ध कर दिया। आंदोलनकारियों ने हजारों की संख्या में नारंगी रिफायनरी पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया था। इंदिरा गांधी की योजना इन आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करते हुए पूरे गुवाहाटी तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में कब्जा कर पेट्रोलियम की आपूर्ति को पुन- बहाल करना थी। वहां पहुंची मेरी बटालियन को नारंगी के सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल पहुंचाने का काम दिया गया था। अन्य 8 बटालियनों को शहर में कर्फ्यू लगाने का काम दिया गया। निर्धारित रात्रि को सबने अपनी-अपनी पोजिशन ली और तड़के नारंगी रिफायनरी में मेरी बटालियन ने भारी कठिनाइयों के बावजूद हजारों आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अन्य सभी बटालियनों ने शहर के हर चौराहे पर कर्फ्यू लागू कराना प्रारंभ किया। लेकिन दिन चढ़ते-चढ़ते हजारों की तादाद में वहां की जनता सड़क पर आ गई। नए आंदोलनकारी पुन- नारंगी रिफायनरी जा पहुंचे तथा इंदिरा गांधी की पूरी योजना विफल कर दी। यह आंदोलन पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी में फैल चुका था, जो असमियों द्वारा अपनी पहचान, अपनी अस्मिता के संरक्षण की खातिर किया जा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान (जो आगे चलकर बांग्लादेश हुआ) से आए विस्थापितों के कारण आबादी की संरचना बदल रही थी। वर्ष 1900 के आसपास पूर्वी बंगाल (जो तब भारत का ही अंग था) से असम की ओर पलायन आरंभ हो गया था। असम में आबादी कम और भूमि अधिक थी तथा वहां के जमींदारों को सस्ते बंगाली श्रमिकों की आवश्यकता थी। देश की आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान से गरीब बंगालियों (अधिकांश मुस्लिम) का असम आना जारी रहा। असम की बराक घाटी मुस्लिम-बहुल हो गई और ब्रह्मपुत्र की निचली घाटी में नई बसाहटें होना शुरू हो गईं। वर्ष 1951 से 2011 के बीच देश की आबादी 235 फीसदी बढ़ी, जबकि इसी दौरान असम की आबादी में 288 फीसदी इजाफा हुआ। स्वतंत्रता के बाद असम में 1956 में गोलपाड़ा जिले के विभाजन को लेकर तथा 1972 में भाषा को लेकर हिंसक घटनाएं हुईं। परंतु अस्सी के दशक का प्रारंभिक आंदोलन बहुत व्यापक था, जिसने पूरे देश का ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आकृष्ट किया। इसी दौर में मेरी बटालियन को गुवाहाटी से हटाकर नलबाड़ी, बरपेटा, कोकराझार, धुबरी और बोंगइगांव आदि के ग्रामीण इलाकों में तैनात किया। वहां रहते हुए मैंने इस आंदोलन की तीव्रता को महसूस किया। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए अनेक समझौता वार्ताएं हुईं और आखिरकार 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी के प्रयासों से असम समझौता हुआ, जिससे आंदोलन पर विराम लगा। हाल ही में असम में एनआरसी को लेकर उठे विवाद के बाद भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अमित शाह ने संसद के इस उच्च सदन में कहा कि 1985 के असम समझौते की आत्मा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) है। वास्तव में इस समझौते में कहा गया था कि 1961 से पहले आए विस्थापितों को पूर्ण नागरिकता दी जाएगी। 1961 से 1971 के बीच आए लोगों को 10 वर्ष तक मताधिकार से वंचित कर उसके बाद नागरिकता दी जाएगी। मुख्य बिंदु 1971 के बाद बांग्लादेश से आए लोगों को वापस किया जाना था। हकीकत यह है कि इस संबंध में कभी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यह समझौता जरूर हो गया, किंतु असम इसके बाद भी शांत नहीं हुआ।

विडंबना यह है कि भारत में राजनीतिक दल यहां तक कि राष्ट्रीय समस्याओं को भी दलगत हित के हिसाब से देखते हैं। बांग्लादेश से पलायन कर यहां आने वाले लोगों का रुझान हमेशा से कांग्रेस की ओर रहा है। पिछले दिनों बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ पार्टी भी उत्पन्न् हुई है। इनकी वजह से हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण हुआ है और इसी का नतीजा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में हुए पिछले कुछ चुनावों में भाजपा को जबर्दस्त सफलता हासिल हुई है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में भाजपा की केंद्र तथा असम सरकार ने एनआरसी का अंतिम मसौदा तैयार किया। इसी मसौदे के आधार पर इस राज्य में रह रहे 40 लाख लोगों की नागरिकता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। हालांकि एनआरसी के इस अंतिम मसौदे पर लोगों से आपत्तियां भी आमंत्रित की गई हैं। एनआरसी के इस अंतिम मसौदे के प्रकाशन से पूरे देश की राजनीति गरमा गई है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूण कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए इसे भाजपा की साजिश करार देते हुए देश में गृहयुद्ध, रक्तपात होने की चेतावनी भी दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि इस रजिस्टर के आधार पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। वैसे भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को निर्वासित किया जाना नामुमकिन-सा लगता है। पूरे उपमहाद्वीप में बांग्लादेश आज हमारा सबसे करीबी साथी है और उसने इस पूरे प्रकरण को भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए दूरी बना ली है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस पूरे मामले के मानवीय पक्ष पर दृष्टि रखे हुए है। लगता यही है कि असम को ऐतिहासिक झंझावात के निशानों के साथ ही रहना होगा। 2019 के लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में असम का ध्रुवीकरण राष्ट्रीय स्तर तक फैल सकता है। ममता बनर्जी इसके माध्यम से जहां एक ओर विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं वे कांग्रेस को हल्का करने का कोई मौका नहीं छोड़तीं। असम का एनआरसी आते ही वे नई दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति के मंच पर केंद्रीय स्थान पाने में जुट गईं। तमाम दलों को लगता है कि अपने वोट बैंक के संरक्षण व संवर्धन के लिए जाति-धर्म के मुद्दे को हवा देनी होगी। असम के एनआरसी के जरिए उन्हें यह मौका मिल गया है।

(लेखक रिटायर्ड आईपीएस हैं और असम में छात्र आंदोलन के दौरान वहां पदस्थ रहे हैं)

विचार मंथन

गंदे पानी के उपयोग में ही है जल संकट का समाधान

वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली, सामाजिक कार्यकर्ता

नदियां जैसे-जैसे आगे बढ़ती हैं, उनमें सीवेज की मात्रा भी बढ़ती जाती है। नतीजतन राह में बाद के राज्यों को प्रदूषित जल मिलता है। आरोप-प्रत्यारोप भी लगते हैं। कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तुरंत बाद ही तमिलनाडु ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक उसे कावेरी जल को प्रदूषित करके भेजता है। ऐसे ही, नीति आयोग की एक बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली पर पानी को गंदा करके भेजने का आरोप लगाया था। सीवेज नदियों में जा रहा है, तभी तो हरिद्वार में गंगा का पानी आचमन लायक भी नहीं है। यमुना की स्थिति तो और ही चिंतनीय है। पवित्र नदियों का भी गंदा होना उनके उद्गम से ही शुरू हो जाता है। इस साल तो गंगोत्री में भी सीवेज उपचार संयंत्र लगाया गया है। इस समय पूरे विश्व में ही, खासकर विकासशील देशों में 80 से 90 प्रतिशत सीवेज बिना उपचार के जल-स्रोतों में डाल दिया जाता है। भारत में केंद्र सरकार भी मानती है कि शहरी क्षेत्रों में ही लगभग 62 प्रतिशत सीवेज सीधे स्थानीय जल प्रणालियों या जल-स्रोतों में डाल दिया जाता है। कहीं-कहीं यह 70 प्रतिशत तक हो सकता है। इससे जल-स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। देश में 75 से 80 प्रतिशत सतही जल का प्रदूषण घरेलू सीवेज के कारण होता है। सीवेज में 99 प्रतिशत से भी ज्यादा जल और बाकी करीब एक प्रतिशत भाग कार्बनिक या अकार्बनिक ठोस का होता है। इसलिए कई देश सीवेज के जल को ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण रहित करने की तकनीक विकसित करने में लगे हैं। व्यावसायिक स्तर पर वे इन तकनीक का निर्यात भी कर रहे हैं। कृषि और उद्योगों में उपचारित सीवेज जल को उपयोग में लाया जा रहा है। इजरायल में आधी सिंचाई उपचारित जल से हो रही है। कुछ जगह तो इसे पेयजल बनाने तक शुद्ध किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहां ऐसी कोई योजना नहीं दिखती। भारत के केवल शहरी क्षेत्रों से प्रतिदिन करीब 62,000 एमएलडी सीवेज पैदा होता है। इस हिसाब से हमारे शहरी क्षेत्रों से प्रतिदिन लगभग 560 हजार लाख लीटर पानी बरबाद होता है। जब हर बूंद पानी के उपयोग संरक्षण का मिशन हो, तो केवल शहरी घरों-कारखानों आदि से इतने पानी का बेकार हो जाना पीड़ादायक है। कुछ जिम्मेदारी हम आत्मानुशासन से संभाल सकते हैं। आंकड़े यह भी हैं कि देश में जितना पानी घरों में पहुंचाया जाता है, उसका 70 प्रतिशत से ज्यादा सीवेज में चला जाता है। भारत में औसतन प्रति व्यक्ति जल की आपूर्ति जब 1,885 लीटर प्रति दिवस थी, तो प्रति व्यक्ति प्रति दिवस सीवेज 1,378 लीटर था। इसमें वह साफ पानी भी होता है, जो हमारे नल खुला छोड़ देने या दाढ़ी बनाते या ब्रश करते समय नल चालू रखने से बह जाता है। इसमें अधिकांश में वह जल होता है, जो हमारे घरों में पीने लायक बनकर पहुंचता है। जल सुरक्षा और सीवेज जल उपचार का सीधा संबंध है। एक तो उपचारित जल का उपयोग परोक्ष रूप से जल की उपलब्धता बढ़ाता है। दूसरा, तीन चरण तक उपचारित सीवेज जल को जल-स्रोतों में छोड़कर स्रोतों के प्रदूषित होने के जोखिम को कम किया जा सकता है। उपचारित सीवेज जल स्वत: ही जल-स्रोतों में पहुंचने के बाद पुन: उपयोग चक्र में आ जाता है। यह भी देखा गया है कि शहरों के आस-पास के किसान, खासकर सब्जी उगाने वाले, गंदी नालियों का पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ जगहों पर इन्हें खरीदा भी जा रहा है। कुछ इसे सब्जियों को धोने के काम में भी ला रहे हैं। ऐसी सब्जियों के खाने से बीमारियों के खतरे खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर सीवेज जल का उपचार दो चरण तक हो, तो कृषि-कार्यों के लिए इसे उपयोग में लाया जा सकता है। हालांकि यहां भी यह ध्यान रखने की जरूरत है कि उपचार तय मानकों के आधार पर ही होना चाहिए, किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। इसमें बचे हुए प्रदूषण का स्तर इतना भर होना चाहिए कि प्रकृति खुद अपनी प्रक्रियाओं से उनसे उबरने की क्षमता रखे। हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं।

जल के इस तरह से उपयोग का काम हमें युद्ध-स्तर पर करना होगा। जल इतना अमूल्य है कि उसे एक बार ही उपयोग करके नहीं गंवाया जा सकता है। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

उत्तर कोरिया को मानवीय सहायता पहुंचाने की योजना का संरा ने किया समर्थन

संयुक्त राष्ट्र।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज अमेरिका द्वारा तैयार किए गए उन उपायों को स्वीकृति दे दी जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि उत्तर कोरिया पर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के कारण वहां पहुंचने वाली मानवीय सहायता बाधित न हो। संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के मुताबिक उत्तर कोरिया की करीब आधी आबादी यानि एक करोड़ लोग अल्पपोषित हैं। पिछले साल यहां खाद्य उत्पादन में कमी दर्ज की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव इस बात पर विशेष रूप से जोर देते हैं कि प्रतिबंधों का असर मानवीय सहायता पर नहीं होना चाहिए लेकिन राहत संस्थानों का तर्क है कि सख्त व्यापार और बैंकिंग कदमों के चलते अधिकारी तंत्र संबंधी रुकावटें पैदा हो रही हैं और जरूरी आपूर्तियों का प्रवाह धीमा हो रहा है। कई हफ्तों तक चर्चा होने के बाद इस प्रस्ताव को आज स्वीकार कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र में नीदरलैंड्स की स्थाई उपप्रतिनिधि लीज ग्रेगोइर वान हैरन ने उम्मीद जताई कि इन दिशा-निर्देशों के जरिए, च्प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना उत्तर कोरियाई लोगों को मानवीय सहायता दिए जाने के संबंध में स्पष्टता मिलेगी।'' नीदरलैंड प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता कर रहा है।

चीन के पहले हाइपरसॉनिक विमान का परीक्षण सफल, दुश्मनों को ऐसे देगा मात

बीजिंग।

चीन ने अपने पहले मिसाइल भेदी हाइपरसोनिक विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह विमान परमाणु हथियारों को ले जा सकता है और अपनी तेज रफ्तार व प्रक्षेपण से मौजूदा पीढ़ी की किसी मिसाइल रक्षा प्रणाली को भेद सकता है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक शुक्रवार को उत्तरपश्चिम चीन में स्थित एक लक्षित सीमा में इस शिंगकांग-2 या स्टारी स्काई-2 का परीक्षण किया गया। यह विमान स्वतंत्र रूप से उड़ा और योजना के अनुसार लक्षित क्षेत्र में उतरा। इसे एक रॉकेट से लांच किया गया और करीब 10 मिनट बाद हवा में छोड़ा गया। चीन एयरोस्पेस साइंस व टेक्नोलॉजी कॉर्प के तहत चीन की एकेडेमी ऑफ एयरोस्पेस एयरोडायनेमिक्स (सीएएए) ने एक बयान में कहा कि उड़ान वाहन 30 किमी की ऊंचाई तक पहुंचा। एक सैन्य जानकार सोंग झोंगपिंग ने बताया कि वेब राइडर एक उड़ान वाहन है, जो वायुमंडल में उड़ता है और अपने हाइपरसोनिक उड़ान द्वारा पैदा हुई शॉक वेब का इस्तेमाल हवा में तेज रफ्तार से जाने के लिए करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, एंटी-मिसाइल रक्षा प्रणालियों की मौजूदा जनरेशन मुख्य रूप से क्रूज और बलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई है, जिनके बारे में पता लगाना धीमा या आसान है और इसी कारण उन्हें रोकना संभव है। लेकिन चीन का नया हाइपसॉनिक विमान इतना तेज उड़ता है कि यह मौजूदा ऐंटी मिसाइल डिफेंस प्रणालियों के लिए चुनौती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, वेवराइडर को किसी भी रॉकेट से लॉन्च किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वेवराइडर परमाणु और पारंपरिक हथियार दोनों ही ले जाने में सक्षम है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस परीक्षण से दिखता है कि चीन अब अमरीका और रूस की तर्ज पर ही खुद को विकसित कर रहा है। सैन्य इस्तेमाल के अलावा इसका आम लोगों या कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन, जिसने इस साल 175 अरब डॉलर का रक्षा बजट पेश किया था, अमरीका, रूस और यूरोपीय संघ से बराबरी के लिए डिफेंस रिसर्च और डिवेलपमेंट में काफी खर्च कर रहा है।

मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने को लेकर कोई नहीं धमका सकता: एंड्रेस

मैक्सिको।

मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने को लेकर देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओबराडोर ने आज कहा कि कोई उनको धमका नहीं सकता। इस साल एक दिसंबर को राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे ओबराडोर ने कहा, ''मैक्सिको एक शक्ति बनने जा रहा है और वह सत्ता के संतुलन को बदल देगा। कोई हमें यह धमकी नहीं दे सकता कि हमारी सीमाएं बंद की जाएंगी या उनका सैन्यकरण किया जाएगा''। गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने देश की सीमा सुरक्षित करने के लिए कई कारणों का उल्लेख किया, जिनमें पिछले साल मैक्सिको में रिकार्ड संख्या में हत्याएं होना प्रमुख कारण था। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 14 मई को मैक्सिको सिटी में ओबराडोर से मुलाकात की थी लेकिन सीमा पर दीवार बनाने के मामले पर तब बात नहीं हुई थी। इसके बाद मैक्सिको के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और अमरीकी राष्ट्रपति के बीच पत्रों के आदान-प्रदान में भी यह मुद्दा नहीं उठाया गया।

इतिहास के सबसे भयंकर सूखे की चपेट में आस्ट्रेलिया

मेलबर्न।

ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। ये वहां इतिहास का अबतक का सबसे भयंकर सूखा है। इसकी सबसे ज़्यादा मार किसानों पर पड़ी है। इस खेत के मालिक ने बताया कि 2010 के बाद से यहां बारिश न के बराबर हुई है।किसानों को अपने पालतू जानवरों के लिए भी खाना जुटाना होता है। इससे उनके खर्चे और बढ़ जाते हैं। एक किसान टॉम वोल्सटन ने कहा, सूखे ने हमारी मुसीबतें बढ़ा दी है. मेरा पूरा दिन खाना जुटाने की कोशिश में निकल जाता है। किसानों की मदद के लिए सरकार अबतक 738 मिलियन डॉलर खर्च कर चुकी है। किसान एश विटनी कहते हैं,मेरी पूरी ज़िंदगी इसी इलाके में गुज़री है लेकिन मैंने ऐसा भीषण सूखा कभी नहीं देखा। परेशान किसानों के लिए सरकार ने मेंटल हेल्थ सर्विस भी शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया में साल 2002 के बाद जुलाई में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों का पेट भरने वाले एक चौथाई कृषि उत्पाद न्यू साउथ वेल्स से आते हैं। वहां पड़े इस सूखे ने पूरे कृषि उद्योग पर असर डाला है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जून में सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जलवायु परिवर्तन इस त्रासदी की अहम वजह है। रॉयटर्स के फोटोग्राफर डेविड ग्रे ने इस सूखी धरती की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं।आसमां से ली गई इस त्रासदी की कुछ तस्वीरें बेहद अद्भुत नज़र आईं।

संक्षिप्त समाचार

इसी सप्ताह लगेगा साल 2018 का आखिरी सूर्य ग्रहण

वॉशिंगटन। साल 2018 का आखिरी सूर्य ग्रहण 11 अगस्त को लगेगा। इससे पहले इसी साल 15 फरवरी और 13 जुलाई को सूर्य ग्रहण लगा था। हालांकि 11 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण इस बार आंशिक होगा जो कि 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगा। भारत में इस सूर्यग्रहण का सूतक काल 10 अगस्त की देर रात 12 घंटे पहले 1 बजकर 32 मिनट पर शुरू हो जाएगा। नासा के अनुसार 2019 में भी तीन सूर्य ग्रहण देखने को मिलेंगे। 2019 में पहला सूर्य ग्रहण 6 जनवरी को, दूसरा 2 जुलाई को और तीसरा 26 अगस्त को पड़ेगा। क्या होता है सूर्य ग्रहण : पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ-साथ अपने सौरमंडल के सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है. दूसरी ओर, चंद्रमा दरअसल पृथ्वी का उपग्रह है और उसके चक्कर लगता है, इसलिए, जब भी चंद्रमा चक्कर काटते-काटते सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब पृथ्वी पर सूर्य आंशिक या पूर्ण रूप से दिखना बंद हो जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण का समयः इस बार का सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 32 मिनट से शुरू होकर शाम 5 बजे खत्म होगा। ग्रहणकाल का सूतक लगभग 12 घंटे पहले लगेगा। हालांकि अंतरराष्ट्रीय समय के अनुसार आंशिक सूर्य ग्रहण 8 बजकर 2 मिनट से शुरू होकर सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर खत्म होगा। सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगाः साल का यह आखिरी सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ पश्चिमी एशिया, साउथ कोरिया, मास्को, चीन जैसे कई देशों के लोग देख पाएंगे। लंदन में सूर्यग्रहण सुबह 9 बजकर 2 मिनट पर शुरू होगा। यहपृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध यानी कि उत्तरी यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया और रूस में दिखाई देगा।

सीरियाः अमरीकी हमलों में मारे गए आईएसआइ के 28 जिहादी

मोसुल। अमरीका की योजना के तहत पूर्वी सीरिया में आईएसआई को पराजित किया जा चुका है। जहां एक तरफ सीरिया का गृहयुद्ध संघर्ष से एक कदम आगे राजनयिक बातचीत में बदल गया है। वहीं पूर्वी सीरिया उन संघर्षों से बाहर आने की कोशिश कर रहा है जिसने उसे तोड़ दिया है। सीरियाई कर्नल का कहना है कि सैन्य कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी। पूर्वी सीरिया में अमरीका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना और सहयोगी लड़ाकों के हमलों में सोमवार को इस्लामिक स्टेट के कम से कम 28 जिहादी मारे गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रमुख रामी अब्देल रहमान ने कहा, 'हवाई हमलों और तोपों से किए गए हमलों में कम से कम 28 आईएस आतंकी मारे गए।' रहमान ने बताया कि गठबंधन सेना और कुर्द तथा अरब लड़ाकों के गठबंधन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने इराक की सीमा से लगते बीर अल-मेलेह क्षेत्र में हमले किए। एक समय सीरिया और इराक के लगभग सभी हिस्सों पर कब्जा जमा चुके आईएस का सीरिया के तीन फीसदी से भी कम क्षेत्र पर कब्जा है। सीरिया में कई अभियान चला कर आईएस को खदेड़ दिया गया है।

नेपालः भूस्खलन में 1 महिला और 7 बच्चों की मौत

काठमांडू। नेपाल में एक सप्ताह के दौरान भूस्खलन से एक महिला और कम से कम सात बच्चों की मौत हो गयी। इस बीच भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ आने के खतरे को देखते हुये अधिकारियों ने सोमवार को चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के बीच काम करते हुये बचाव दल के कर्मचारी राजधानी काठमांडू से 310 किलोमीटर दूर भेरी शहर में अभी भी एक लापता लड़के की तलाश कर रहे हैं। भेरी में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी कृष्णा प्रसाद खाटीवाड़ा ने फोन पर रायटर को बताया कि सेना और पुलिसकर्मी मलबे में 12 वर्षीय लड़के की तलाश कर रहे हैं। भूस्खलन में मरने वाले बच्चों की उम्र तीन से 11 वर्ष के बीच है। नेपाल के ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में जून से सितंबर में भूस्खलन और अचानक बाढ़ आना आम बात है। मौसम कार्यालय के अधिकारी समीर श्रेष्ठ ने बताया कि मंगलवार को मध्य और पश्चिमी नेपाल के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश होने की वजह से और भूस्खलन एवं बाढ़ आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि भारत की सीमा से लगे नेपाल के निचले तराई क्षेत्र के निवासियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है क्योंकि कई नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।

तालिबान के हमले में सेना के 4 जवान, 4 महिलाओं की मौत

काबुल। तालिबान ने पश्चिमी फराह प्रांत में एक सैन्य जांच चौकी पर हमला कर दिया जिसमें चार जवान मारे गये और छह घायल हो गए। अफगानिस्तान के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। प्रांतीय गर्वनर के प्रवक्त मोहम्मद नासेर मेहरी ने बताया कि बाला बुलुक जिले में हमला सोमवार देर रात शुरू हुआ और मंगलवार सुबह तक जारी रहा। मेहरी ने बताया कि अफगान वायु सेना को मदद के लिए बुलाया गया और वायुसेना के हवाई हमलों में 19 तालिबानी लड़ाके मारे गए और 30 घायल हो गए। एक अन्य घटना में पूर्वी लोगर प्रांत में सेना और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ में चार महिलाएं मारी गयी और चार बच्चे घायल हो गए। प्रांतीय परिषद के सदस्य हसीबुल्लाह स्तानिकजई ने बताया कि प्रांत की राजधानी पुली अलीम के निकट सोमवार दोपहर में मुठभेड़ हुई। हमले को लेकर तालिबान की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आयी है जिसने हाल के महीनों में अफगानिस्तान में अपने हमले तेज कर दिए हैं।

अमेरिका प्रतिबंध लगाने की घोषणा से फिर अलग-थलग पड़ा: ईरान

तेहरान।

ईरान ने सोमवार को कहा कि देश में राजनीतिक उथल-पुथल के मद्देनजर इस्लामी गणराज्य पर फिर से प्रतिबंध लगाने की घोषणा करके अमेरिका अलग-थलग पड़ गया है। अर्द्ध-सरकारी समाचार एजेंसी आईएसएनए के अनुसार विदेश मंत्री मोहम्मद जावद जरीफ ने पत्रकारों से कहा,''बेशक, अमेरिकी धमकाने और राजनीतिक दबाव बनाकर कुछ व्यवधान पैदा कर सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि वर्तमान दुनिया में अमेरिका अलग-थलग है।' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2015 के परमाणु समझौते से मई में बाहर होने के निर्णय के बाद अमेरिका मंगलवार को फिर से ईरान पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय संघ के राजनयिक प्रमुख फेडेरिया मोगेरिनी ने एक संयुक्त बयान में कहा,''अमेरिका द्वारा फिर से प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार होने पर हमें गहरा अफसोस है।'' इस बयान पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के भी हस्ताक्षर थे। ईरान पर ये प्रतिबंध दो चरणों में सात अगस्त और पांच नवम्बर को लगाए जाने है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2015 के परमाणु समझौते से बाहर होने के बाद वह (अमेरिका) ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगा रहा है और इन्हें कड़ाई से लागू भी किया जाएगा।

सऊदी अरब ने कनाडाई राजदूत को किया बर्खास्त, अपने राजदूत को बुलाया वापस

रियाद।

सऊदी अरब ने अपने आंतरिक मामलों में ''हस्तक्षेप'' का आरोप लगाकर कनाडा के राजदूत को बर्खास्त करने और अपने राजदूत को भी वापस बुलाने की आज घोषणा की साथ ही उसने कनाडा के साथ व्यापारिक संबंधों पर भी रोक लगा दी है।

सऊदी अरब ने कनाडाई राजदूत को देश छोडने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। यह कदम शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की आक्रामक विदेश नीति को दर्शाता है। गौरतलब है कि रियाद में कनाडाई दूतावास ने जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की थी जिसके बाद सऊदी अरब ने यह कदम उठाया। सऊदी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, ''कनाडा का रुख सऊदी अरब के आतंरिक मामलों में खुल्लमखुल्ला और जबरदस्त हस्तक्षेप है। मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब घोषणा करता है कि वह विचार-विमर्श के लिए कनाडा में अपने राजदूत को वापस बुला रहा है।

हमारा मानना है कि देश में कनाडा के राजदूत की जरूरत नहीं है और उन्हें अगले 24 घंटे के अंदर जाने का आदेश दिया गया है।' साथ ही मंत्रालय ने कहा कि आगे की कार्रवाई के अधिकार को बरकरार रखते हुए कनाडा के साथ सभी नए व्यापारिक और निवेशात्मक लेनदेन पर रोक लगाई जाती है। कनाडा ने गत सप्ताह कहा था कि वह देश में महिलाओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों को लेकर ''बहुत चिंतित'' है।

ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री ने बुर्का पहनी महिलाओं को बताया 'लेटर बॉक्स'

लंदन। ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने बुर्के को 'दमनकारी' बताते देते हुए यह लिबास पहनी महिलाओं को 'लेटर बॉक्स' करार दिया है। इसके बाद आज उनकी आलोचना की गई। 'द डेली टेलीग्राफ' में रविवार को अपने नियमित स्तंभ में कंजरवेटिव पार्टी के सांसद ने कहा कि वह डेनमार्क की तर्ज पर बर्के को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के खिलाफ हैं। उन्होंने लिखा, '' अगर आप मुझसे कहें कि बुर्का दमनकारी है तो मैं आपके साथ हूं... मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह बिल्कुल हास्यास्पद है कि लोग आने-जाने के लिए लेटर बॉक्स तरह दिखने का विकल्प चुनते हैं।'' उन्होंने ब्रिटेन में कारोबारी और सरकारी एजेंसियों को 'ड्रेस कोड' लागू करना चाहिए और लोगों के चेहरे देखने की इजाजत मिलनी चाहिए। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ने उनसे माफी की मांग करते हुए उनपर अति दक्षिणपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जबकि विपक्षी लेबर पार्टी के सांसदों ने इस्लामोफोबिया को भड़काने का आरोप लगाया। लेबर पार्टी की नाज शाह ने कहा, ''बोरिस जॉनसन के नस्लीय अपमान पर हंसा नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री टेरीजा मे को इस्लामफोबिया की निंदा करनी चाहिए और बोरिस जॉनसन को माफी मांगनी चाहिए।''

पाक की नई सरकार भी सिंधु जल विवाद लेकर जाएगी विश्व बैंक

इस्लामाबाद।

14 अगस्त को इमरान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जहां देश में नई सरकार का गठन होगा वहीं पाक का राजनीतिक परिवेश भी बदल जाएगा। पाकिस्तान के द न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कि पाकिस्तान की नई सरकार भारत के साथ सिंधु नदी विवाद को लेकर फिर से विश्व बैंक के दरवाजे पर दस्तक देगी। पाक सरकार 1960 के इस समझौते को लेकर मध्यस्थता पंचाट गठित करने की मांग भी करेगी। जम्मू कश्मीर में किशनगंगा (330 मेगावॉट) और रातले (850 मेगावॉट) पनबिजली परियोजनाओं के भारत के डिजाइन पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान ने पिछले साल भी वर्ल्ड बैंक का रुख किया था। किशनगंगा प्रॉजेक्ट झेलम की सहायक नदी, जबकि रातले प्रॉजेक्ट चेनाब नदी से जुड़ा है। संधि में इन दोनों नदियों के साथ सिंधु नदी को पश्चिमी नदियों के तौर पर परिभाषित किया गया है। इन नदियों के पानी के इस्तेमाल पर पाकिस्तान को किसी बंदिश का सामना नहीं करना पड़ता है। भारत इस मुद्दे पर निरीक्षण के लिए एक निष्पक्ष एक्सपर्ट की मांग करता रहा है। पाकिस्तान के कार्यवाहक जल संसाधन मंत्री सैयद अली जफर से जब पूछा गया कि विश्व बैंक पाकिस्तान के निवेदन पर सकारात्मक प्रक्रिया नहीं दे रहा जबकि भारत के समर्थन में फैसले आ रहे हैं तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान में नई सरकार सत्ता में आ रही है। चीन, रूस और तुर्की भी यह मान रहे हैं कि पानी पाकिस्तान के लिए बड़ा मुद्दा है, इसलिए विश्व बैंक को इसपर पंचाट गठित करनी चाहिए। बता दें कि दोनों देशों के इस संधि पर सवाल उठने लगे थे। सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत में संधि के तहत नदियों से मिलने वाले पानी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था।

विश्व बैंक का कहना है कि हमने दोनों देशों के बीच विवाद के समाधान के लिए काम किया है।

सूरत। महावीर हिंदी विद्यालय पांडेसरा में मेहंदी स्पर्धा का आयोजन किया गया। जिसने स्कूल की बालिकाओं ने विभिन्न प्रकार की मेहंदी हाथों पर बना कर अपनी प्रतिभा दिखाई।

सूरत। मकान खरीद कर बिल्डरों से शोषित हुए लोगों ने कलेक्टर ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया।

पांडेसरा बना गुनेहगारों का स्वर्ग

पांडेसरा के बडोद समीप झाड़ियों मे बालिका का मृतदेह मिलन से सनसनी

सूरत। पांडेसरा विस्तार लगता है कि गुनेहगारो के लिए स्वर्ग के समान हो गया है पांडेसरा विस्तार में ही पिछले कई दिनों से खुले मैदानों और झाड़ियों में कई लोगों की हत्या कर फेंकी गई लाशें मिली है जिसमें चर्चित कुछ दिन पहले ही 10 साल की लड़की का शव मिलना था। यह लाश पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी लेकिन पुलिस ने आरोपियों को ढूंढ निकाला। लेकिन फिर भी गुनेहगारों के मन में पुलिस के लिए रत्ती भर भी भय नहीं दिख रहा है। क्योंकि बड़ोद गांव में लगभग 8 साल की बच्ची का हत्या करके जो शव मिला है और उसके शरीर पर जो जख्म के निशान है इससे साबित होता है कि उसकी हत्या की गई है। गुनहगारों के लिए पांडेसरा विस्तार स्वर्ग के समान हो गया है जहां पर आरोपी आरोप करने के बाद शव को बड़ी आसानी से ठिकाने लगा सकता है और खुलेआम घूमते फीरता है।

पांडेसरा पुलिस सीमा वडोद, प्रेम प्वाइन्ट चोकड़ी समीप झाड़ी मे से एक अज्ञात मासूम बालिका की संदिग्ध लाश मिलने से पांडेसरा पीआई सहित पुलिस का काफिला घटना स्थल पर पहुंच गया। पुलिस की प्राथमिक जांच व फोरेन्सिक जांच में बालिका के शरीर पर से घाव के करीब 30 निशान मिले है। उसके सिर के बाघ में गंभीर चोट के निशान भी मिले है। हालांकि अन्य जांच हेतु विविध सेम्पल फोरेन्सिक जांच हेतु भेजे गये है। समग्र घटना के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह वडोद चार रास्ता प्रेम प्वाइन्ट चोकड़ी समीप झाडी में से करीब चार वर्षीय मासूम बालिका की संदिग्ध लाश मिलने की जानकारी पांडेसरा पुलिस को मिली। जानकारी मिलते ही पाआई. के.बी. झाला तथा उच्छ अधिकारियों सहित पुलिस का काफिला घटना स्थल पर पहुंच गया। पुलिस की प्राथमिक जांच व फोरेन्सिक रिपोर्ट में बालिका के शरीर पर से करीब 30 घाव के निशान मिले है। जिससे सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या की गई होने की पुष्टि हुई है। हालांकि विशेष जांच हेतु विविध सेम्पल फोरेन्सिक लेब मे भेज दिया गया है। पुलिस पंचनामा कर लाश का सिविल हॉस्पिटल में फोरेन्सिक रिपोर्ट कराया। घटना स्थल पर लोगों का जमावड़ा हो गया था। पुलिस ने बालिका के पजिनों की खोजबिन शुरु की है।

अठवा में जीओ टावर पर चढकर युवक का आत्महत्या का प्रयास

न्युज चेनल मालिकों पर सवा दो लाख हड़पने का लगाया आरोप

सूरत। अठवालाइन्स क्षेत्र चोपाटी के पास स्थित मोबाइल के टावर पर मंगलवार दोपहर एक युवक चढ जाने से भारी अफरा-तफरी मच गई। घटना के चलते लोगों का टोला एकत्रित हो गया। स्थानिय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड़ को जानकारी दी। फायर ब्रिगेड़ के जवानों ने घटना स्थल पर पहंच कर युवक को समझाने का प्रयास किया। हालांकि युवक ने पुलिस कमिश्नर को बुलाने की जीद की। पुलिस कमिश्नर के घटना स्थल पर पुहंचने के बाद युवक को नीचे उतारा गया। जहां उसने एक नीजी चेनल के संचालकों ने उसके साथ सवा दो लाख रुपए लेने का आक्षेप लगाय।

घटना के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर 12 बजे अठवालाइन्स चौपाटी के सामने स्थित जीओ मोबाईल के टावर पर एक युवक चढा गया। प्रथम तो वह लोगों को मानसिक रोगी लगा। हालांकि युवक अधिक उंचाई तक चढ जाने पर लोगों ने पुलिस और फायर को इस बारे में जानकारी दी। जिससे उमरा पुलिस घटना स्थल पर पहंचकर युवक को नीचे उतराने के लिए फायर की सहायाता ली। पुलिस और फायर के जवानों ने युवक को नीचे उतरने के लिए काफी समझाया लेकिन युवक ने पुलिस कमिश्नर को बुलाने की जीद की। जिसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर सतीष शर्मा को होने पर वे स्वयं घटना स्थल पर पहुंचे और युवक को नीचे उतरने के लिए कहा। पुलिस कमिश्नर की बात मानकर युवक नीचे उतरा। इस युवक का नाम मगन और वह भेस्तान क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर को उसने बताया कि उसके भवन का निमार्ण कार्य जारी था जहां आकर एक न्युज चेनल के संचालकों ने धमकी देकर उसके पास से कुल सवा दो लाख रुपये ऐंठ लिये।

जागेश्वर आश्रम के महंत की हत्या के आरोप में पति-पत्नी गिरफ्तार

भरुच। जिले के वागरा स्थित जागेश्वर आश्रम के महंत की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पति-पत्नी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के मुताबिक भरुच जिले की वागरा तहसील के जागेश्वर मीठी तलाई आश्रम के छोटे महाराज दयानंद स्वामी का गत 31 जुलाई को उनके कमरे में रखे पलंग के नीचे से शव बरामद हुआ था। लहूलुहान हालत में मिले शव मिलने के बाद सुरेश मगनभाई ने गुरु पर्णिमा के दिन आश्रम में ठहरे हेमंत शर्मा और जयश्री उर्फ राधिका पर दयानंद स्वामी की हत्या के संदेह व्यक्त किया था। सुरेश ने पुलिस को बताया कि दंपत्ति मध्य प्रदेश का मूल निवासी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निवास कर रहा है। एलसीबी पुलिस की एक टीम वाराणसी रवाना हो गई। जहां वाराणसी पुलिस की मदद से अस्सी घाट क्षेत्र से वीरेन्द्र उर्फ हेमंत रविशंकर शर्मा और उसकी पत्नी ज्योति उर्फ जयश्री उर्फ राधिका शर्मा को गिर तार कर लिया। पुलिस दंपत्ति को लेकर गुजरात लौट आई और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में पता चला कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दोनों दयानंद स्वामी के आश्रम में ठहरे थे। 29 जुलाई को रात करीब 9 बजे दयानंद स्वामी ने वीरेन्द्र को दुकान से धनिया और जीरा लेने भेज दिया। वीरेन्द्र के जाने के बाद आश्रम में उसकी पत्नी और दयानंद स्वामी अकेले रह गए। लहूलुहान हालत में मिले शव मिलने के बाद सुरेश मगनभाई ने गुरु पर्णिमा के दिन आश्रम में ठहरे हेमंत शर्मा और जयश्री उर्फ राधिका पर दयानंद स्वामी की हत्या के संदेह व्यक्त किया था। सुरेश ने पुलिस को बताया कि दंपत्ति मध्य प्रदेश का मूल निवासी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निवास कर रहा है। एलसीबी पुलिस की एक टीम वाराणसी रवाना हो गई। जहां वाराणसी पुलिस की मदद से अस्सी घाट क्षेत्र से वीरेन्द्र उर्फ हेमंत रविशंकर शर्मा और उसकी पत्नी ज्योति उर्फ जयश्री उर्फ राधिका शर्मा को गिर तार कर लिया। एकांत का लाभ उठाते हुए दयानंद ने ज्योति शर्मा के साथ छेड़छाड़ और जोरजबर्दस्ती शुरू कर दी। जिसके प्रतिकार में ज्योति ने निकट पड़ी एक लाठी उठाकर दयानंद के सिर में दे मारी। वार इतना जोरदार था कि दयानंद लहूलुहान होकर वहां ढेर हो गया। जिसे देख ज्योति भी बेहोश हो गई। दुकान से लौट वीरेन्द्र पत्नी ज्योति बेहोश और दयानंद को लहू से लथपथ देख चौंक पड़ा। ज्योति को होश में लाने के बाद दोनों ने दयानंद के शव को एक क बल में लपेटकर पलंग के नीचे बने दराज में रख दिया और वहां से दोनों फरार हो गए।

अहमदाबाद में दिखा पाटीदार पावर

100 करोड़ दान मांगा, जमा हुए 150 करोड़

अहमदाबाद। पाटीदारों की कुलदेवी उमिया माता के मंदिर और क यूनिटी कॉ प्लेक्स के लिए रु. 100 करोड़ का दान मांगा गया था। लेकिन केवल 3 घंटों में रु. 150 करोड़ रुपए जमा हो गए। दरअसल रविवार को पाटीदार समाज के लोगों ने विश्व उमिया फाउंडेशन की बैठक हुई थी। जिसमें अहमदाबाद में बनाए जानेवाले उमिया माता के मंदिर के लिए दान देने की अपील की गई थी। अपील का ऐसा असर हुआ कि लोगों दिन खोलकर तीन घंटों में रु. 150 करोड़ से खजाना छलका दिया। जिसमें सबसे अधिक रु. 51 करोड़ का दान मुंबई निवासी पटेल परिवार ने दिया था। कुछ वर्ष पहले उत्तरी गुजरात के मेहसाणा से मुंबई स्थायी हुए इस परिवार ने 7 साल पहले गोरेगांव में उमिया माता के मंदिर निर्माण के लिए जमीन दे चुका है। इसके अलावा हरिद्वार में उमियाधाम बनाने के लिए भी इस परिवार ने रु. 71 लाख का दान किया था। विश्वभर के कडवा पाटीदारों को एक मंच पर लाने वाले विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा सुशिक्षित, सामर्थ्यवान एवं संगठित समाज निर्माण के संकल्प के साथ अहमदाबाद के वैष्णोदेवी सर्कल के निकट 100 बीघा जमीन में 1000 करोड़ रुपए की लागत 5 वर्ष में पाटीदार ए पावरमेंट हब तैयार किया जाएगा। जिसमें माता उमिया का 80 फूट ऊंचा भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर पर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए समाज उपयोगी अत्याधुनिक भवन का निर्माण किया जाएगा।

विश्व उमिया फाउंडेशन के मु य संयोजक सीके पटेल ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि वैष्णादेवी के निकट जासपुर लीलपुर मार्ग पर संस्था की ओर से 100 बीघा जमीन में निर्माण होनेवाला यह मंदिर वैश्विक स्तर के पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। मंदिर पाटीदार समाज का इतिहास भी पेश किया जोगा। इस कै पस में यूनिवर्सिटी, स्वास्थ्य केन्द्र, होस्टेल इत्यादि की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा कै पस में अस्पताल, स्पोर्ट्स एवं कल्चर कॉ प्लेक्स, एज्यूकेशन इंस्टीट्यूट एवं युवक-युवतियों के लिए होस्टेल बनाई जाएगी। रु. 1000 करोड़ की लागत से पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा। सीके पटेल ने बताया कि उमिया फाउंडेशन ने रु. 100 करोड़ एकत्र करने की अपील की थी। लेकिन दाताओं ने दिल खोलकर रु. 150 करोड़ से खजाना छलका दिया। किसी सामाजिक कार्य में इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम एकत्र की गई है।

आज से बारिश का दूसरे राउंड की संभावना

सूरत। मौसम विभाग ने गुजरातभर में मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटों में बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सक्रिय होगा, जिससे 24 घंटों में देश के अलग अलग राजयों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। जबकि गुजरात समेत पश्चिम के अन्य राज्यों में 8 अगस्त के पश्चात मॉनसून के दोबारा सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। गौरतलब है मॉनसून के के प्रारंभ में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में मूशलारिश अब तक नहीं हुई। बारिश नहीं होने से किसानों में अपनी फसल को लेकर चिंता व्याप्त है। यदि समय पर बारिश नहीं हुई तो किसानों के बीज और मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी।

इशरत केस : बंजारा और अमीन की डिस्चार्ज अर्जी खारिज

अहमदाबाद। सीबीआई की विशेष अदालत ने इशरत जहां एन्काउंटर केस में गुजरात के पूर्व डीजीपी डीजी बंजारा और पुलिस अधीक्षक एनके अमीन की डिस्चार्ज याचिका को आज खारिज कर दिया7 कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को मुकर्रर की है।

गुजरात के बहुचर्चित इशरत एन्काउंटर केस में पूर्व पुलिस महानिदेशक पीपी पांडेय को सीबीआई की विशेष अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। पीपी पांडे पर अन्य पूर्व पुलिस अधिकारियों के साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा इशरत जहां मामले में साजिश, अवैध रूप से कारावास और हत्या के आरोप थे। पीपी पांडे इस मामले के पहले आरोपी थे जिन्हें कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया था। पीपी पांडेय के इस मामले में बरी होने के बाद डीजी बंजारा और एनके अमीन ने भी डिस्चार्ड अर्जी की थी। जिसका इशरत जहां की माता ने कड़ा विरोध किया था। मामले की जांच कर रही सीबीआई पहले ही बंजारा और अमीन की याचिका का विरोध कर चुकी है। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि डीजी बंजारा और एनके खिलाफ आपराधिक षडयंत्र का केस साबित हो चुका है। डीजी बंजारा के आदेश पर ही एन्काउंटर को अंजाम दिया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए डीजी बंजारा और एनके अमीन की डिस्चार्ज याचिका को खारिज करते हुए अगली सुनवाई आगामी 7 सितंबर को मुकर्रर की है। गौरतलब है अहमदाबाद अपराध शाखा के अधिकारियों ने 15 जून, 2004 को शहर के बाहरी इलाके में महाराष्ट्र की 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा इशरत जहां, उसके दोस्त जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई, जीशान जोहर और अमजद राणा को कथित फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। गुजरात पुलिस ने उस वक्त कहा था कि मारे गये लोग लश्कर के आतंकी थे और वे लोग तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते थे।

महादेव मीडिया
रोहताश यादव 9924144499, 7015339195
वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)
हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।
304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com